



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 932]
No. 932]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 28, 2004/कार्तिक 6, 1926
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2004/KARTIKA 6, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2004

का. आ. 1198(अ).— जबकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट(उपक्रम का अंतरण एवं निरसन)अधिनियम 2002(2002 का 58) (जिसे यहां इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) 29, अक्टूबर, 2002 को लागू हुआ ;

तथा जबकि उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट उपक्रम उक्त धारा 2 के खंड (क) में उल्लिखित प्रशासक को अंतरित किया गया था तथा विहित किया गया था ;

तथा जबकि नियत किए गए दिन अर्थात् 1 फरवरी, 2003 से तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के कार्यों एवं कारोबार के संबंध में भारतीय यूनिट ट्रस्ट को प्रदत्त सभी राजकोषीय एवं अन्य रियायतें, लाइसेंस, लाभ, विशेषाधिकार एवं छूटें उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में प्रदत्त मानी गई हैं ;

तथा जबकि नियत किए गए दिन अर्थात् 1 फरवरी, 2003 से पांच वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में प्राप्त किसी आय, लाभ अथवा मुनाफे अथवा प्राप्त किसी राशि के संबंध में प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में कोई आयकर अथवा कोई अन्य कर संदेय नहीं है ;

तथा जबकि उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (1) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट उपक्रम के अंतरण एवं विहितीकरण को पूंजी लाभ के प्रयोजनों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अर्थ में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अंतरण नहीं माना जाएगा ;

तथा जबकि उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट उपक्रम के अंतरण एवं विहितीकरण से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अन्तर्गत किसी स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान की देनदारी नहीं होगी ;

तथा जबकि विनिर्दिष्ट उपक्रम की सभी योजनाओं के मोचन पर तथा निवेशकों को संपूर्ण राशि के भुगतान पर उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रशासक से अपने पद को तत्काल छोड़ा जाना अपेक्षित है ;

तथा जबकि अपना पद छोड़ने पर प्रशासक द्वारा केन्द्र सरकार अथवा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी संस्था अथवा अधिकारी को धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रशासक के रूप में अपना पद छोड़ने की तिथि से तत्काल पूर्व तिथि को विनिर्दिष्ट उपक्रम का प्रतिनिधित्व करने वाली तथा उससे संबंधित सभी परिसंपत्तियों तथा संपत्तियों का सुपुर्द किया जाना अपेक्षित है, जो उसके स्वामित्व, अभिरक्षा एवं नियंत्रण में हैं ;

तथा जबकि अब प्रशासक द्वारा अपना पद छोड़ा जाना संभावित है तथा अपना पद छोड़ने पर वह केन्द्र सरकार को अथवा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी संस्था या अधिकारी को प्रशासक के रूप में अपना पद छोड़ने की तिथि से तत्काल पूर्ववर्ती तिथि को विनिर्दिष्ट उपक्रम को प्रतिनिधित्व करने वाली तथा उससे संबंधित उन सभी परिसंपत्तियों तथा संपत्तियों का स्वामित्व सुपुर्द कर देगा जो उसके स्वामित्व, अभिरक्षा तथा नियंत्रण में है ;

तथा जबकि केन्द्र सरकार अथवा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी संस्थान या अधिकारी को [उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) में यथा उल्लिखित] निम्न की अनुमति देने या प्रदान करने में कठिनाईयों को दूर करना अब आवश्यक हो गया है :-

- (क) धारा 12 के तहत विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में पहले से ही प्रदत्त रिआयतें, लाइसेंस, लाभ, विशेषाधिकार तथा छूटें,
- (ख) धारा 13 के तहत विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में प्रशासक को पहले से अनुमत कर छूट अथवा लाभ, तथा
- (ग) उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत यथा मामला, प्रशासक या विनिर्दिष्ट उपक्रम को पहले से ही अनुमत स्टाम्प शुल्क से छूट,

अतः अब भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण तथा निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्न आदेश करती है, नामतः --

1. संक्षिप्त नाम तथा आरम्भण :- (1) इस आदेश को भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण तथा निरसन) (कठिनाईयों का समाधान) आदेश, 2004 कहा जाएगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. केन्द्र सरकार अथवा धारा 8 की उप-धारा (2) में उल्लिखित इसके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किसी संस्था या अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12 से 14 के तहत उपलब्ध की जाने वाली रियायतें, लाइसेंस, लाभ, विशेषाधिकार तथा छूटें :- (1) प्रशासक या विनिर्दिष्ट उपक्रम को धारा 12 के तहत प्रदत्त या अनुमत सभी रियायतें, लाइसेंस, लाभ, विशेषाधिकार तथा छूटें केन्द्र सरकार अथवा इसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी संस्था या अधिकारी [उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) में यथा उल्लिखित] को उन्हीं शर्तों तथा निबंधनों पर अनुमत की जानी जारी रहेंगी जिनपर वे प्रशासक द्वारा पद छोड़ने से पूर्व प्रशासक या विनिर्दिष्ट उपक्रम को अनुमत थीं।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 13 के तहत पहले से अनुमत सभी कर छूटें या लाभ केन्द्र सरकार को या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी संस्था या अधिकारी को [उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में यथा उल्लिखित] उन्हीं शर्तों तथा निबंधनों पर अनुमत किए जाने जारी रहेंगे जिनपर वे प्रशासक द्वारा पद छोड़ने से पूर्व विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में प्रशासक को अनुमत थे तथा केन्द्र सरकार या ऐसी संस्थाओं या अधिकारियों को ऐसी कर छूट या लाभ केवल अकालातीत अवधि के लिए ही अनुज्ञेय होंगे।

(3) उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत विनिर्दिष्ट उपक्रम को स्टाम्प शुल्क से समस्त छूटें केन्द्र सरकार या इसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी संस्था या अधिकारी को [उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में यथा उल्लिखित] उन्हीं शर्तों तथा निबंधनों पर अनुमत की जानी जारी रहेगी जिनपर प्रशासक द्वारा पद छोड़ने से पूर्व विनिर्दिष्ट उपक्रम को स्टाम्प शुल्क से छूट अनुमत थी।

[फा. सं. 5/31/2004—यूटीआई एण्ड जेपीसी]
यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 28th October, 2004

S.O. 1198(E).— Whereas the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002 (58 of 2002) (hereafter referred to as the said Act) came into force on the 29th day of October, 2002;

AND WHEREAS the specified undertaking referred to in clause (i) of section 2 of the said Act had been transferred to, and vested in, the Administrator referred to in clause (a) of said section 2;

AND WHEREAS all fiscal and other concessions, licences, benefits, privileges and exemptions granted with effect from the appointed day, being the 1st February, 2003, to the Unit Trust of India in connection with the affairs and business of the specified undertaking of the Trust under any law for the time being in force are deemed to have been granted in relation to the specified undertaking under section 12 of the said Act;

AND WHEREAS no income-tax or any other tax is payable by the Administrator in relation to the specified undertaking for a period of five years from the appointed day, being the 1st February, 2003, in respect of any income, profits or gains derived, or any amount received in relation to the specified undertaking under sub-section (1) of section 13 of the said Act;

AND WHEREAS the transfer and vesting of the specified undertaking referred to in clause (i) of section 2 of the said Act, shall not be construed under sub-section (2) of section 13 of the said Act as a transfer within the meaning of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) for the purposes of capital gains;

AND WHEREAS the transfer and vesting of the specified undertaking referred to in clause (i) of section 2 of the said Act, shall not be liable to the payment of any stamp duty under the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899);

AND WHEREAS the Administrator is required immediately, on redemption of all the schemes of the specified undertaking and the payment of entire amount to investors, to vacate his office under sub-section (1) of section 8 of the said Act;

AND WHEREAS the Administrator is required on vacation of his office, to deliver, to the Central Government or any institution or officer specified by it, possession of all assets and properties representing and relatable to the specified undertaking which are in his possession, custody and control on the date immediately preceding the date on which he vacates his office as the Administrator under sub-section (1) of section 8;

AND WHEREAS the Administrator is now likely to vacate the office and on vacation of his office, shall deliver to the Central Government or any institution or officer specified by it, the possession of all assets and properties representing and relatable to the specified undertaking which are in his possession, custody and control on the date immediately preceding the date on which he vacates his office as the Administrator;

AND WHEREAS it has now become necessary to remove the difficulties in allowing or extending to the Central Government or any institution or officer specified by it (as referred to in sub-section (2) of section 8 of the said Act),-

(a) the concessions, licences, benefits, privileges and exemptions under section 12, already granted in relation to the specified undertaking,

(b) the tax exemption or benefits already allowed to the Administrator in relation to the specified undertaking under section 13, and

(c) the exemption from stamp duty under section 14 of the said Act already allowed to the Administrator or the specified undertaking, as the case may be,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 24 of the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002 (58 of 2002), (hereafter referred to as the said Act) the Central Government hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) (Removal of Difficulties) Order, 2004.

(2) It shall come into force at once.

2. Concessions, licences, benefits, privileges and exemptions under sections 12 to 14 of the said Act to be available to the Central Government or any institution or officer specified by it referred to sub-section (2) of section 8.- (1) All concessions, licences, benefits, privileges and exemptions granted or

allowed under section 12 to the Administrator or specified undertaking, shall continue to be allowed to the Central Government or any institution or officer specified by it, (as referred to in sub-section (2) of section 8 of the said Act), on the same terms and conditions on which the Administrator or the specified undertaking were allowed before vacation of office by the Administrator.

(2) All tax exemptions or benefits already allowed under section 13 of the said Act shall continue to be allowed to the Central Government or any institution or officer specified by it, (as referred to in sub-section (2) of section 8 of the said Act), on the same terms and conditions on which the Administrator in relation to the specified undertaking were allowed before vacation of office by the Administrator and any such tax exemption or benefit shall be allowed to the Central Government or such institutions or officers for the unexpired period only.

(3) All exemptions to the specified undertaking from stamp duty under section 14 of the said Act shall continue to be allowed to the Central Government or any institution or officer specified by it (as referred to in sub-section (2) of section 8 of the said Act), on the same terms and conditions on which the specified undertaking was allowed exemption from stamp duty before vacation of office by the Administrator.

[F. No. 5/31/2004-UTI & JPC]

U. K. SINHA, Jt. Secy.

3242 G7/04-2